ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292RNI
REG. NO. UPBIL/2014/66218 **PP. No.- 98-100**

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-18, No.-IV, Issues-34, YEAR-Oct-Dec. 2024

राजनीतिक और प्रशासनिक भ्रष्टाचार के बदलते स्वरूप

डॉ0 करूण कुमार गुप्ता

असिस्टेन्ट प्रोफेसर–समाजशास्त्र, रामभजन पी0जी0 कॉलेज, चकहुसेन, थलईपुर, मऊ (उ0प्र0) भारत

Received-05.11.2024, Revised-11.11.2024, Accepted-16.11.2024 **E-mail : karungupta292@gmail.com**

सारांशः ***वर्तमान समय में देश के लिए भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या बनी हुई है। अगर हम सोच रहे है कि भ्रष्टाचार केवल सार्वजनिक सेवाओं में ही है तो ऐसा बिलकुल ही नही है। आज भ्रष्टाचार सर्वत्र सर्वव्यापक हो गया है। आज भ्रष्टाचार से न तो राजनीतिक क्षेत्र अछुता है और न प्रशासनिक क्षेत्र। इसका परिणाम यह है कि आज भ्रष्टाचार केवल देश की आर्थिक प्रगति एवं सामाजिक विकास को ही नुकसान नही पहुंचा रहा है, बल्कि देश की एकता, अखण्डता, सुरक्षा को भी संकट उत्पन्न कर रहा है। जनसाधारण को इससे होने वाली परेशानियां अवर्णनीय है। यह व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित कर रहा है। परिणामतः समाज में सर्वत्व व्याप्त भ्रष्टाचार के विषाणु से जनता पूरी तरह से क्षुब्ध एवं त्रस्त है। देश में लोकतंत्र व शासनतंत्र में भ्रष्टाचार की छाया भविष्य के लिए चेतावनी है। जिससे सरकार को सजग होने की जरूरत है। यह देश के सम्यक विकास में बहुत बड़ी बाधा है।***

कुंजीभूत शब्द– भ्रष्टाचार, सर्वव्यापक, अवर्णनीय, लोकसेवक, अकर्मण्यता, राजनीतिक क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्र, क्षुब्ध एवं त्रस्त

भारतीय संविधान में राज्य के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए लोकसेवक शब्द का प्रयोग किया गया है। संविधान के अनुसार संसदीय प्रजातंत्र में राजनेता एवं अधिकारी/कर्मचारी को लोकसेवक कहा जाता है और अधिकारी/कर्मचारी जनता के सेवक के रूप में कार्य करते है लेकिन आज स्थिति यह बनी हुई है कि कतिपय स्थानों पर व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अकर्मण्यता के कारण यह अवधारणा साकार नही हो पा रही है। हर जगह हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार का बोलबाला है।

हाल ही में एक मामला मध्य प्रदेश से आया है जहां परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा द्वारा किया ग्रया भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। "मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग से पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। शुक्रवार सुबह से ग्वालियर में उसके पैतृक घर समेत प्रदेश में कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। बहोड़ापुर इलाके के विनय नगर सेक्टर– 2 में सौरभ शर्मा के बंगले पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी के लिए पहुंची। घर का मुख्य दरवाजा बंद कर दिया गया। बंगले के अंदर और बाहर हथियारों से लैस सी0आर0पी0एफ0 के जवानों की तैनाती दिखी। घर के अंदर करीब एक दर्जन अधिकारी कमरे से लेकर बाथरूम का कोना–कोना छान रहे है। इससे पहले सौरभ शर्मा के ठिकानों और उसके साथी चंदन की कार से करीब 300 किलो सोना चांदी और करोड़ों रूपये कैश बरामद हो चुके है।"[1]

जहां तक प्रशासनिक सेवा में भ्रष्टाचार का प्रश्न है मेरा मानना है कि इसके लिए जनता भी कम दोषी नही है। अधिकांश लोगों में घूस देने की सहज प्रकृति सी हो गई है तथा वे स्वयं को सुरक्षित रखते हुए किसी भी लफड़े में पढ़ने की बजाय येन–केन प्रकारेण अपना काम निकालना चाहते है चाहे इस कार्य हेतु उन्हे नैतिक मूल्यों की तिलांजली ही क्यूं न देनी पडे। इन्हीं सब कारणों से जनता और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच दलाल उत्पन्न हो गये है। खेद जनक परिदृश्य यह है कि एक तरफ से घूस दी जा रही है तो दूसरे तरफ से घूस निःसंकोच स्वीकार की जा रही है, वर्तमान समय में यह परम्परा का रूप धारण कर रहा है। जैसे लगता है कि भ्रष्टाचार हमारे जीवन का दर्शन बन चुका है। आज ये स्थिति बन चुकी है कि हमने विश्वास और प्रगति की सीमा अपने एवं अपने परिवार तक केन्द्रित कर ली है। अपने और अपने परिवार के लिए धन अर्जित करना, साधन व सुविधाएं जुटाना ही जीवन का एक मात्र लक्ष्य बन चुका है। ऐसे घोटाले अक्सर देखने को मिलते है। बहुत से घोटाले तो सबूतों के अभाव में सरकारी फाइलों में दबी रह जाती है।

"उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रिश्वतखोर राजस्व विभाग में है। भ्रष्टाचार निवारण संगठन (एंटी करप्शन ब्यूरों) के आंकड़े भी यही बताते है। वर्ष 2017 से अब तक 340 सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत लेते एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया। उन्हे जेल भेजा जिसमें 135 राजस्व विभाग के थे जिनके खिलाफ कार्यवाही हुई। वही पुलिस विभाग दूसरे स्थान पर रहा, 45 पुलिस कर्मियों को रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा गया।

पांच साल में 340 गिरफ्तारः भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा पांच साल के दौरान रिश्वत लेते हुए 340 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जिसमें राजस्व और पुलिस विभाग के अलावा 160 लोग षिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत आदि विभागों के थे। एंटी करप्शन ने इन पांच वर्ष के दौरान 52 लाख रूपये से अधिक रिश्वत की रकम रंगे हाथों लोगों को गिरफ्तार कर उनसे बरामद की।

सीधे रिश्वत लेने से बचने का करने लगे है प्रयासः भ्रष्टाचारी भी अब सीधे रिश्वत की रकम लेने से बचने का प्रयास करने लगे है। वह रिश्वत लेने के लिए अलग–अलग तरीके अपनाते है। तीसरे व्यक्ति के माध्यम से रकम लेने का प्रयास करते है। पीड़ित को संम्बन्धित व्यक्ति के पास रकम देकर आने को कहते है जो कि विभाग का न होने के चलते पकड़े जाने पर भी उन पर आंच न आए। मगर, लालच उन्हें इसमें फंसा देता है। पीड़ित द्वारा किसी और को रकम देने से माना करने पर वह रिश्वत खुद ले लेते है। रकम पकड़ाते ही सलाखों की पीछे चले जाते है।"[2]

"मीटर बदलवाने के नाम पर 35 हजार रूपये की रिश्वत लेते जे0ई0 को मुरादाबाद से आई एंटी करप्शन की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। टीम ने जे0ई0 के खिलाफ सैफनी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। सैफनी के ग्राम भजनपुर निवासी नासिंर ने एंटी करप्शन मुरादाबाद में शिकायतकी थी, जिसमें बताया था कि उनके घर करीब 6 साल पहले मीटर लगा था। वह कियी अन्य के

अनुरूपी लेखक/ संयुक्त लेखक

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-18, No.-IV, Issues-34, YEAR-Oct-Dec. 2024

नाम से लगा दिया गया। वह मीटर अपने नाम से लगवाने और पुराने मीटर को हटवाने के लिए सैफनी बिजली घर के जे0ई0 विकास संतोषी से मिले। जे0ई0 उन्हे काफी समय से टहलाता रहा, बाद में मीटर बदलने के बदले 35 हजार रूपये की मांग करने लगा।

एंटी करप्शन टीम ने बिछाया जाल– शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने उसे रंगे हाथ पकड़ने के लिए जाल बिछाया। शुक्रवार को भ्रष्टाचार निवारण संगठन मुरादाबाद के निरीक्षक सुखवीर सिंह भदौरिया टीम के साथ सैफनी आए। शिकायतकर्ता को कलर लगे रूपये देकर जे0ई0 के पास भेजा।

रिश्वत के पैसे लेते ही एंटी करप्शन टीम ने जेई को दबोचा– जेई ने रूपये देने के लिए भूड़ा गेट मोड़ के पास लतीफी चाय एंड कोल्ड ड्रिंक स्टोर के सामने बुलाया। जेई वहां अपनी स्विफ्ट डिजायर कार में बैठा था। उसने कार में जैसे ही रिश्वत के पैसे लिए, तब ही एंटी करप्शन टीम ने उसे दबोच लिया। आरोपित जेई मूल रूप से बरेली के थाना सुभाष नगर में कालीचरन मार्ग का रहने वाला है। वह विभाग में 20 सितम्बर 2008 को नियुक्त हुआ था।"[3]

स्पष्ट है कि अपराध हर क्षेत्र में व्याप्त है। प्रशासनिक अधिकारी घूस लेने से बाज नही आ रहे है। इन्ही सब के चलते भ्रष्टाचार पर अंकुष लगाने हेतु उ0प्र0 के मुख्यमंत्री योगी यादित्यनाथ ने प्रदेश भर से राज्य कर विभाग के सबसे भ्रष्ट और खराब छवि वाले अधिकारियों की लिस्ट मंगवानी प्रारम्भ कर दिया है।

स्पष्ट है कि छोटे अधिकारी से लेकर बड़ें अधिकारियों तक हर तरफ भ्रष्टाचार व्याप्त है। 29 अप्रैल 2017 को जागरण एप में छपी रिर्पोट के अनुसार देष में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कर्नाटक राज्य में है। "नई दिल्ली (जेएनएन)। देष के जिन राज्यों में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है उनकी सूची में कर्नाटक टॉप पर है। इस बात का खुलासा 11वी इंडिया करप्शन स्टडी 2017 रिर्पोट में कहा गया है। सरकारी कार्यो को कराने के लिए दिये जाने वाले धूसों के आधार पर भ्रष्ट राज्यों की सूची तैयार की गयी है।

"सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार वाले राज्यों में कर्नाटक के बाद आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडू, महाराष्ट्र, जम्मू–कष्मीर और पंजाब का नम्बर है। हिमांचल प्रदेश, केरल और छत्तीसगढ़ सबसे कम भ्रष्टाचार वाले राज्यों की सूची में है। नीति आयोग के सेंटर फार मीडिया स्टडीज की 11वीं इंडिया करप्शन स्टडी 2017 रिपोर्ट में कहा गया है कि इन राज्यों में सार्वजनिक सेवाओं के लिए जनता को घूस देना पड़ा है। देश के 29 मे से 20 राज्यों में किये गये सर्वे के आधार पर हिमांचल प्रदेश, केरल और छत्तीसगढ़ को सबसे कम भ्रष्ट राज्य माना गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्वे में करीब एक तिहाई लोगों ने माना कि पिछले साल उन्हे कहीं न कहीं रिश्वत देनी पड़ी। सर्वेक्षण में गॉव और शहरी क्षेत्र के 3000 लोगों की राय ली गयी। इनमें से आधे से अधिक ने माना कि नोटबन्दी के दौरान धूसखोरी में कमी आयी थी। रिर्पोट में आकलन किया गया है कि 20 राज्यों के लोगो ने 10 सार्वजनिक सेवाओं के लिए 6350 करोड़ रूपये की रिश्वत 2017 में दी। वर्ष 2005 में लोगों नें 20500 करोड़ रूपये रिश्वत दी थी इस साल कराये गये अध्ययन में 53 फीसदी लोगों ने रिश्वत देने की बात कबूल की थी।

सरकारी काम कराने के लिए दिये जाने वाले धूसों के आधार पर तैयार रिर्पोट में कहा गया है कि देश में भ्रष्टाचार घट रहा है लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। पिछले साल 31 फीसद लोगों को स्कूल, अदालत, बैंक या अन्य कार्यो के लिए 10 रूपये से लेकर 50 हजार रूपये तक की रिश्वत देनी पड़ी। 2005 में 53 फीसद लोगो को रिश्वत देनी पड़ती थी। यानी भ्रष्टाचार में 22 फीसद की कमी आयी है।

कहां कितने लोगों ने दी रिश्वत– कर्नाटक– 77.0 फीसद, आन्ध्र प्रदेश– 74.0 फीसद, तमिलनाडु– 68.0 फीसद, हिमांचल प्रदेश– 03.0 फीसद"[4]

यू0पी0 में भ्रष्ट अफसरों की अब खैर नही है। उनकी मुष्किलें बढ़ने वाली है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश भर से राज्य विभाग के सबसे भ्रष्ट और खराब छवि वाले अधिकारियों की लिस्ट मंगाई है। प्रमुख सचिव राज्य कर एम0 देवराज ने इस संबंध में समीक्षा बैठक के दौरान सभी जोनल आयुक्तों और संयुक्त आयुक्तों को निर्देश दिए। हर जिले में सचल दल और विशेष जांच दल (एस0आई0वी0) को एक–एक सर्वाधिक भ्रष्ट अफसर के नाम मांगे गए है, साथ ही साथ अधिकारियों एवं कर्मचारियों से उनकी निजी संपत्ति का व्यौरा भी मांगना शुरू कर दी है।

स्पष्ट है कि उ0प्र0 के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक साहसिक एवं सकारात्मक कदम उठाया है इसकी जितनी भी प्रसंशा की जाये कम है। अब समय आ चुका है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करते हुए स्वयं को इस भ्रष्टाचार से पूर्णतः मुक्त कर अन्य को भी इस हेतु प्रेरित करे तथा एक भ्रष्टाचार विहिन, प्रगतिशील आदर्श देश के निर्माण में सहयोग करें। उ0प्र0 के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहीं से भी भ्रष्टाचार होने के संबंध में जानकारी प्राप्त होने पर तुरन्त जांच बैठा दे रहे है।

लखनऊ (आससे) राजभवन खण्ड में बिल्डर के लिए नियम बदलने और अमान्य मानचित्र पर बिजली कनेक्शन देने के मामले में मुख्यमंत्री कार्यालय ने जांच बैठा दी है। मामले की जांच के लिए दो जांच कमेटियों का गठन किया गया है। राजभवन खण्ड में बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए नियम बदलने व अमान्य मानचित्र पर बहुमंजिला इमारत में बिजली कनेक्शन स्वीकृत करने के मामले में सी0एम0 दफ्तर ने जांच बैठा दी है। इसमें घालमेल, फर्जीवाड़ा करने वाले इंजीनियरों की जांच के बाद रिर्पोट भी मांगी है। सी0एम0 दफ्तर से पॉवर कॉरपोरेषन मुख्यालय शक्ति भवन पत्र पहुंचा दिया गया है। उम्मीद है कि सोमवार को यह पत्र मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के एम0डी0 को भेजा जायेगा। एम0डी0 की ओर से दोनो प्रकरण में दो जांच कमेटी गठित की गई है। इसमें एक की जांच हो चुकी मगर रिर्पोट फाईल नही की गई। राजभवन और मोहनलालगंज खण्ड के तहत सुल्तानपुर रोड पर बिजली लाईनो को बनाने का ठेका लेने वालों को घालमेल करने वाले इंजीनियरों को बचाने में जुटे थे। सी0एम0 दफ्तर से आये पत्र ने

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-18, No.-IV, Issues-34, YEAR-Oct-Dec. 2024

खासकर अमान्य जिला पंचायत के मानचित्र पर बहुमंजिला इमारत में 990 किलो वाट का आवासीय व व्यावसायिक बिजली लोड स्वीकृत करने वाले इंजीनियर राजभवन के पूर्व एक्स0ई0एन0 धर्मेन्द्र सक्सेना, पूर्व कैन्ट एस0डी0ओ0 शिवनाथ शुक्ला जो वर्तमान में पॉवर कॉरपोरेशन अध्यक्ष के शिविर कार्यालय में तैनात बतौर एक्स0ई0एन0 में हडकंप मचा दिया है। अमर उजाला ने अंसल सुशान्त गोल्फ सिटी स्थित व्यावसायिक केन्द्र को रोशन करने के लिए बिल्डर की खातिर नियम बदलने के खेल का खुलासा किया था। इसमें जेई अरविन्द, एस0डी0ओ0 पुरूषोत्तम कुमार ने व्यावसायिक केन्द्र को 33000 करंट की बजाय 11000 करंट के नेटवर्क पर 2600 किलोवाट बिजली लोड स्वीकृत करने के लिए राजभवन खण्ड के पूर्व एक्स0ई0एन0 धर्मेन्द्र सक्सेना को पत्र भेजा गया था। लोड स्वीकृत करने की पैरवी एस0डी0ओ0 ने की थी। जांच बैठी तो सिन्डिकेट एक्स0ई0एन0 को बचाने व जेई, एस0डी0ओ0 को फंसाने का खेल शुरू हो गया। अमान्य मानचित्र पर बहुमंजिला इमारत 990 किलोवाट लोड स्वीकृत कराने वाले षिवनाथ शुक्ला को कॉरपोरेशन अध्यक्ष के शिविर से अब तक नही हटाया गया, जिन्होने फर्जीवाड़ा कराया, इस फर्जीवाड़े में जेई0 एस0डी0ओ0, एक्स0ई0एन0, तकनीकी सहायक आदि फंसें है।"[5]

देखा जाय तो 2014 के बाद से एन0डी0ए0 की सरकार के आने से भ्रष्टाचार के मामलों में कमी है। एन0डी0ए0 की सरकार के पहले देश में घोटालों की लाइन लगी रहती थी। पर अब यदा कदा ही सुनने को मिलता है। जहां तक मुझे लगता है कि देश में भ्रष्टाचार को रोकरने के मामले में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार और उत्तर–प्रदेश राज्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार अब तक की सरकारों में सबसे श्रेष्ठ सरकार है।

भ्रष्टाचार एक ऐसा व्यवहार है, जिसमें सरकारी कर्मचारी अपने व्यक्तिगत स्वार्थो या यू कहें कि लाभ के लिए अपने सार्वजनिक कर्तव्यों से विचलित होकर नियमों का उल्लंधन करता है जिससे कुछ विषेष प्रकार के व्यक्तिगत लाभ प्राप्त हो सके।

वास्तविकता यह है कि राजनीतिक भ्रष्टाचार की छांव में प्रशासनिक भ्रष्टाचार भी फलता फूलता नजर आ रहा है। पहले के समय में लोक प्रशासन का क्षेत्र सीमित था, फलस्वरूप भ्रष्टाचार न के बराबर होता था परन्तु वर्तमान समय में लोक प्रशासन के क्षेत्र का अत्यधिक विकास हो जाने के कारण भ्रष्टाचार की मात्रा मों बेहिसाब वृद्वि हुई है।

"प्रदेश की डबल इंजन की सरकार में भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया है। नियमों को और कड़ा किया जा रहा है भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे फेंका जा रहा है ताकि लोग गड़बड़ियां करने की हिम्मत न जुटा सकें। यह बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही।

शनिवार को केजीएमयू के 120वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार के पास पैसे की कोई कमी नही है। मेडिकल संस्थान नये विभाग खोले। नई तकनीकी विकसित करें। जो भी योजना शुरू करें, उसे समय पर जरूर पूरा करें। पहले लोग सरकार से पैसे तो ले लेते थे लेकिन काम नही करते थे। बजट को पीएलए अकाउन्ट में डाल देते थे। भाजपा सरकार बनी तो खजाना खाली था। हमने पीएलए अकाउन्ट में जमा पैसा विभागों से मंगाया। उससे कर्मचारियों का वेतन दिया विभागों को जनता से जुड़े मुद्दे समय पर पूरा करने के निर्देष दिये इससे जनता का भरोसा बढ़ा है।" 6

निष्कर्ष– यह सत्य है कि भारतीय राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से भ्रष्टाचार के गिरफ्त में है। चूंकि वर्तमान केन्द्र सरकार इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने का प्रयास जरूर कर रही है, और बहुत हद तक सफल भी होती दिख रही है। प्रशासनिक अधिकारियों के मन में एक खौफ या कहें तो डर जरूर रहता है। किसी भी भ्रष्टाचार को करने से पहले अब अधिकारी भ्रष्टाचार करने से पहले कई बार सोचते है और पकड़े जाने पर उसके दुष्परिणाम को एक बार जरूर सोच लेते है। अन्त में हम यह कहेंगें कि इस भ्रष्टाचारी रूपी दैत्य को समाप्त करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी भूमिका को एक बार जरूर सोचना एवं समझना चाहिए। जब तक प्रशासनिक अधिकारी अपने व्यक्तिगत लाभों का परित्याग नही करेंगें तब तक भ्रष्टाचार को कभी समाप्त नही किया जा सकता है। यही सत्य है और इस सत्य को हम सभी को स्वीकार करना होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. 27 दिसम्बर 2024 लाइव हिन्दुस्तान ग्वालियर मध्यप्रदेश न्यूज।
2. 30 सितम्बर 2022 जागरण न्यूज आगरा उत्तर प्रदेश।
3. 20 दिसम्बर 2024 जागरण न्यूज रामपुर उत्तर प्रदेश।
4. 29 अप्रैल 2017 जागरण न्यूज, जागरण हिन्दी न्यू राष्ट्रीय।
5. 30 दिसम्बर 2024 आज वाराणसी उत्तर प्रदेशं।
6. 22 दिसम्बर 2024 हिन्दुस्तान वाराणसी, उत्तर प्रदेश।

*****